इमराना जलाल
अध्यक्ष
निरीक्षण पैनल

IPN REQUEST RQ 18/07
18 दिसंबर, 2018

पंजीकरण का नोटिस

निरीक्षण के लिए द्वितीय निवेदन

भारत: कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (P132173)

सार

1. 12 दिसंबर, 2018 को, निरीक्षण पैनल ("पैनल") को कम आय वाले राज्यों के लिए भारत ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (RWSSP i.e. Rural Water Supply and Sanitation Project) ("परियोजना") का निरीक्षण करने के लिए एक अनुरोध ("अनुरोध") प्राप्त हुआ। भारत के झारखंड राज्य के एक गाँव से 130 संथाली और हो आदिवासी समुदाय के सदस्यों ("अनुरोधकर्ता") द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किया गया था। अनुरोधकर्ताओं ने गोपनीयता की माँग की।

2. अनुरोधकर्ता का मुद्दा है उनके गांव में RWSSP ("स्कीम") के तहत वितपोषित जल आपूर्ति योजना के हिस्से के रूप में एक उन्नत भंडारण जलाशय (ESR i.e. elevated storage reservoir) का निर्माण। उनका दावा है कि ESR उनकी सामुदायिक भूमि पर बनाया जा रहा है, जिसका संथाली और हो आदिवासी समुदाय के सदस्यों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान में मुफ्त में मिलने वाले पानी के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने योजना के पर्यावरणीय प्रभाव और अपर्याप्त पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन का भी मुद्दा उठाया। अनुरोधकर्ताओं ने स्थानीय भाषाओं में परामर्श और सूचना प्रकटीकरण के अभाव का भी दावा किया, और प्रतिशोध का मुद्दा भी उठाया।

3. 21 सितंबर, 2018 को, पैनल को संथाली आदिवासी समुदाय के सदस्यों से परियोजना के निरीक्षण के लिए पहला अनुरोध मिला था। अनुरोधकर्ताओं का मुद्दा उनकी सामुदायिक भूमि में एक जल उपचार संयंत्र के निर्माण को लेकर था, जो उनके ऐतिहासिक और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव, परामर्श और सूचना प्रकटीकरण के अभाव का भी दावा किया, साथ ही प्रतिशोध के डर का भी। पहले अनुरोध के पंजीकरण का नोटिस 5 नवंबर, 2018 को जारी किया गया था। पैनल ने 11 दिसंबर, 2018 को पहले अनुरोध पर प्रबंधन प्रतिक्रिया प्राप्त की थी। चूंकि दोनों अनुरोध एक ही परियोजना से संबंधित समान मुद्दे उठाते हैं, पैनल उन्हें अर्थव्यवस्था और दक्षता के कारणों से संयुक्त रूप से संसाधित करने का इरादा रखता है।

परियोजना

4. ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (P132173) US$1 बिलियन की परियोजना है, जिसमें से US$500 मिलियन के बराबर वित्त इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) प्रदान करता है और शेष भारत सरकार करती है। परियोजना को 30 दिसंबर, 2013 को मंजूरी दी गई थी, और अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 है।

5. परियोजना का विकास उद्देश्य "*विकेन्द्रीकृत वितरण प्रणाली के माध्यम से लक्षित राज्यों में चयनित ग्रामीण समुदायों के लिए पाइप जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना और तुरंत और प्रभावी रूप से एक योग्य संकट या आपातकाल के लिए सहभागी राज्यों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाना है।*"[1]

6. परियोजना के चार घटक हैं: ए) क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास; बी) बुनियादी ढाँचे का विकास; सी) परियोजना प्रबंधन का समर्थन; और डी) आकस्मिक आपातकालीन प्रतिक्रिया। अनुरोध, घटक बी से संबंधित है। परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (PAD i.e. Project Appraisal Document) में कहा गया है कि यह घटक "*जल आपूर्ति और स्वच्छता कवरेज में सुधार के लिए निवेश का समर्थन करेगा, जिसमें नए बुनियादी ढाँचे का निर्माण और मौजूदा योजनाओं का पुनर्वास और संवर्द्धन शामिल है।*"[2]

7. PAD के अनुसार, जल आपूर्ति निवेश में जल स्रोत को मजबूत करना और जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण गतिविधियाँ शामिल होंगी। जबकि अधिकांश बस्तियों को स्थानीय भूजल स्रोतों का उपयोग करके एकल ग्राम योजनाओं द्वारा सेवा प्रदान करने की उम्मीद की जाती है, दस्तावेज बताते हैं कि "*बहु ग्राम योजनाएँ (MVSs i.e. Multi Village Schemes), जो मुख्य रूप से सतह के जल स्रोतों पर निर्भर हैं, उन बस्तियों के लिए अपनाई जाएंगी जहां स्थानीय स्रोत या तो टिकाऊ नहीं हैं या स्वीकार्य गुणवत्ता के नहीं हैं।*"[3]

8. परियोजना को पर्यावरण श्रेणी बी में निर्दिष्ट किया गया था और निम्नलिखित सुरक्षा नीतियों को चलाती है: पर्यावरणीय आकलन (OP/BP 4.01), प्राकृतिक बस्तियाँ (OP/BP 4.04), वन (OP/BP 4.36), स्थानीय लोग (OP/BP 4.10) और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग (OP/BP 7.50) पर परियोजनाएं।

अनुरोध

9. यह अनुरोध भारत के झारखंड राज्य के एक गाँव के 130 संथाली और हो आदिवासी समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि परियोजना से उनके "*सामूहिक सांस्कृतिक संसाधन, आजीविका और स्वायत्तता*" प्रभावित हुए हैं। उन्होंने नीचे वर्णित नुकसानों का आरोप लगाया है।

10. **सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव**। अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि परियोजना "*स्थानीय समुदायों की आवश्यक सांस्कृतिक प्रथाओं की निरंतरता के लिए खतरा है।*" उनका कहना है कि ESR जो उनकी सामुदायिक भूमि पर बनाया जा रहा है, उस भूमि का गाँव के निवासियों के लिए सांस्कृतिक महत्व है। उनके अनुसार, इस स्थल पर वार्षिक समारोह होते हैं, साथ ही एक बलिदान समारोह और भोज भी होता है, जो हर पांच साल में होता है।

11. अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि समुदाय और झारखंड राज्य के लिए ESR स्थान एक महत्वपूर्ण शहादत स्थल है, जो इस समुदाय के पुरुषों के सम्मान में है, जिन्होंने झारखंड राज्य के लिए संघर्ष में अपना जीवन दिया। साइट पर समुदाय द्वारा वार्षिक शहादत दिवस मनाया जाता है। वे बताते हैं कि परियोजना ने शहीदों की प्रतिमा को शमन उपाय के रूप में बनाया है। हालांकि, वे कहते हैं कि इस मुद्दे के बारे में समुदाय से परामर्श नहीं किया गया था, और वे मरने वाले सदस्यों के लिए मूर्तियों को खड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं। उनकी संस्कृति के अनुसार, शहीदों की याद में पत्थरों या शिलाखंडों को रखा जाना चाहिए था।

12. अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए राज्य को किसी मान्यता प्राप्त *अनुसूचित क्षेत्र*[4] से निगम को भूमि हस्तांतरित करना असंवैधानिक है। उनका आरोप है कि परियोजना के दस्तावेज गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि योजना सरकारी भूमि पर बनाई जाएगी। उनके अनुसार, इन दस्तावेजों ने सामुदायिक भूमि पर निर्मित संरचनाओं पर विचार नहीं किया।

---

[1] परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज, **p.3.**
[2] **Ibid., p.5.**
[3] **Ibid.**

13. अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि परियोजना को भौतिक सांस्कृतिक संसाधन नीति को ट्रिगर करना चाहिए था। उनके अनुसार, परियोजना में भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था, जो OP 4.11 की अवज्ञा में है।

14. **आर्थिक प्रभाव**। अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि वर्तमान में उनके पास नि:शुल्क जल की पर्याप्त उपलब्धता है और उन्हें पाइप वाले जल की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क है कि परियोजना के बाद उन्हें जल के लिए भुगतान करना होगा और यह उनके समुदाय को और दरिद्र बनाएगा।

15. **शहर सीमा के विस्तार से संबंधित प्रभाव**। अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि यह योजना प्रस्तावित शहरी ढेर योजना का एक प्रमुख घटक है और इसका उपयोग निकटवर्ती शहर की शहर सीमा का विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह विस्तार "*स्थानीय समुदाय पर एक विनाशकारी प्रभाव होगा [...], जिसमें उनकी संस्कृति, संसाधनों तक पहुंच, और पारंपरिक प्रशासन अभ्यासों पर प्रभाव शामिल हैं।*" यह कानूनी सुरक्षा को भंग करने के लिए एक उत्प्रेरक होगा जो एक *अनुसूचित क्षेत्र* के रूप में उनका समुदाय वहन करता है, और गैर-प्रांतीयता की ओर ले जाएगा, वे इशारा करते हैं।

16. **अपर्याप्त सामाजिक मूल्यांकन और स्थानीय जन योजना**। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि परियोजना ने OP 4.10 के गैर-अनुपालन में स्थानीय सामुदायिक संसाधनों पर इस विशेष योजना के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन नहीं किया। वे बताते हैं कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का स्थानीय लोगों पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए और न ही परियोजना विकल्पों की जांच के लिए एक सामाजिक मूल्यांकन तैयार किया गया था, और यह कि "*बैंक प्रबंधन स्थानीय समुदायों के जोखिमों का उचित मूल्यांकन करने के कदम उठाने में विफल रहा।*" उनके अनुसार, झारखंड स्थानीय जन योजना ने गलत निष्कर्ष निकाला कि "*कार्यक्रम हस्तक्षेप स्थानीय समुदायों को प्रभावित नहीं करेंगे*" और स्थानीय समुदायों पर योजना के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के किसी भी उपाय पर ध्यान नहीं दिया गया था।

17. **परामर्श**। अनुरोधकर्ता बताते हैं कि पर्यावरण आकलन-पर्यावरण प्रबंधन ढांचे, सामाजिक मूल्यांकन और स्थानीय जन योजना के लिए परामर्श केवल झारखंड राज्य स्तर पर और परियोजना के लिए समग्र रूप से किए गए थे, न कि विशिष्ट योजनाओं के लिए। उनके अनुसार, "*इन परामर्शों ने परियोजना-प्रभावित लोगों पर परियोजना के नियोजित घटकों के प्रभावों को समझने का समुचित प्रयास नहीं किया।*" वे बताते हैं कि बैंक प्रबंधन और कार्यान्वयन अधिकारियों ने उनके समुदाय से परामर्श नहीं किया और *"समुदाय के गहन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ी भूमि पर योजना के एक प्रमुख घटक का निर्माण होने के बावजूद समुदाय के विचारों को ध्यान में रखने का थोड़ा प्रयास भी नहीं हुआ।"*

---

[4] अनुसूचित क्षेत्र आधिकारिक रूप से अधिसूचित क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जो आदिवासी आबादी, भौगोलिक सुगठितपन और सामाजिक और आर्थिक अविकसितता की महत्वपूर्ण उपस्थिति द्वारा चिह्नित हैं।

18. वे आगे बताते हैं कि एक *अनुसूचित क्षेत्र* के रूप में, उनके गांव में राष्ट्रीय कानून के तहत विशेष सुरक्षा है और उनके गांव में कोई भी विकास गतिविधि शुरू करने के लिए एक ग्राम सभा[5] प्रस्ताव एक पूर्व-शर्त है। उनका आरोप है कि संबंधित ग्राम सभा ने उनके गांव में ESR के निर्माण के लिए सहमति नहीं दी, बल्कि इसका विरोध करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए हैं। उनके अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के दौरान आदिवासी संस्थानों को "*दरकिनार*" किया गया था।

19. अनुरोधकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि OP 4.10 के साथ गैर-अनुपालन में व्यापक सामुदायिक समर्थन हासिल किया गया था। वे समझाते हैं कि इस योजना को "*जबरदस्त विरोध के बावजूद समुदाय पर थोपा गया है*" और "*कोई स्वतंत्र, पूर्व और सूचित परामर्श प्रक्रिया नहीं हुई है।*"

20. **सूचना का प्रकटीकरण**। अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि "कार्यान्वयन प्राधिकरण ने कभी भी समुदाय को कोई दस्तावेज़ प्रदान नहीं किया है।" वे दावा करते हैं कि योजना के बारे में जानकारी न तो स्थानीय रूप से और न ही बैंक की वेबसाइट पर बताई गई है, जिसमें केवल परियोजना के बारे में पूरी जानकारी है। वे बताते हैं कि समुदाय केवल कुछ परियोजना दस्तावेजों को एक्सेस करने में सक्षम था, जो दूसरे गांव के सदस्यों द्वारा साझा किए गए थे। हालाँकि, उनके अनुसार, कोई भी दस्तावेज़ हिंदी, संथाली या हो भाषा में उपलब्ध नहीं थे।

21. **प्रतिशोध**। अनुरोधकर्ता कहते हैं कि उन्हें "योजना के बारे में शिकायत करने से [...] डर लगता है।" वे कहते हैं कि समुदाय के सदस्यों को "भयानक परिणामों" की धमकी दी गई थी जब उन्होंने अपनी जमीन पर ESR के निर्माण का विरोध करने की कोशिश की थी।

22. **पर्यावरणीय प्रभाव और अपर्याप्त पर्यावरणीय आकलन**। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि परियोजना को श्रेणी बी के बजाय एक पर्यावरण श्रेणी ए निर्दिष्ट की जानी चाहिए थी, क्योंकि इसका पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा, और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उनका तर्क है कि परियोजना ने एक "*पर्याप्त पर्यावरणीय मूल्यांकन*" का संचालन नहीं किया और यह कि एक पर्यावरणीय मूल्यांकन- जबकि झारखंड राज्य के लिए पर्यावरण प्रबंधन ढांचा तैयार किया गया था, इसने उपयोजना के संभावित प्रतिकूल प्रभाव की जांच नहीं की। वे OP 4.01 के साथ गैर-अनुपालन में "*उपयोजनाओं की निगरानी उचित करने के लिए बैंक प्रबंधन की ओर से विफलता*" मानते हैं।

23. अनुरोधकर्ता चिंता व्यक्त करते हैं कि योजना पास की नदी से महत्वपूर्ण मात्रा में पानी निकालेगी और क्षेत्र के जल विज्ञान और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। उनके अनुसार, यह विशेष रूप से उन स्थानीय गांवों को प्रभावित करेगा जहां पानी के स्थानीय निकाय कई सांस्कृतिक प्रथाओं का एक प्रमुख घटक हैं। वे जल उपचार प्रक्रिया से उत्पन्न कीचड़ से प्रदूषण के बारे में भी चिंतित हैं, जो विषाक्त हो सकता है, और दावा करते हैं कि परियोजना दस्तावेजों में कीचड़ प्रबंधन पर कोई जानकारी नहीं है।

---

[5] *ग्राम सभा* एक गाँव के सभी लोगों की एक सामान्य सभा है, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, और गाँव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। एक ग्राम सभा प्रस्ताव एक मुद्दे के पक्ष में बहुसंख्यक वोट है।

24. अगले चरण। अनुरोधकर्ता पैनल से "*बैंक नीति के उल्लंघन की पुष्टि की [...] तत्काल जांच करने के लिए कहते हैं।*" वे अनुरोध करते हैं कि विश्व बैंक: (i) व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन किए जाने तक योजना के निर्माण को निलंबित कर दे; (ii) इस योजना और आसपास के क्षेत्रों में योजनाबद्ध अन्य लोगों के संचयी हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव को देखने के लिए एक स्वतंत्र जल विज्ञान विशेषज्ञ नियुक्त करें; (iii) हिंदी, हो और संथाली भाषाओं में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का खुलासा करे; (iv) उनकी सांस्कृतिक और शहादत स्थल को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा और पुनर्विभाजन प्रदान करे; (v) सरकार से अनुरोध है कि वह अपने सामुदायिक संसाधनों के अनियमित भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और; (vi) पाइप वाले जल की आवश्यकता का आकलन करने के लिए प्रभावित गांवों के सभी पारंपरिक प्रमुखों और ग्राम सभाओं के साथ एक स्वतंत्र परामर्श करे।

प्रारंभिक उचित उद्यम

25. अनुरोध प्राप्त होने के बाद, पैनल ने अपने प्रारंभिक उचित उद्यम को संचालित किया और सत्यापित किया कि अनुरोध पंजीकरण के लिए स्वीकार्य मानदंड को पूरा करता है, जो निम्नानुसार है:

26. अनुरोध निष्ठुर, बेतुका या गुमनाम नहीं है, और भारत के झारखंड राज्य के एक गांव से 130 संथाली और हो आदिवासी समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जहां परियोजना स्थित है।

27. अनुरोधकर्ताओं ने बैंक प्रबंधन को पिछले पत्राचार के साक्ष्य प्रदान किए और पैनल के साथ कई ई-मेल साझा किए। 10 अक्टूबर, 2018 को, अनुरोधकर्ताओं ने बैंक प्रबंधन को परियोजना के मुद्दे उठाता हुआ एक ई-मेल भेजा था। 15 अक्टूबर, 2018 को, बैंक प्रबंधन ने कथित तौर पर अघोषित समुदाय का दौरा किया। 29 अक्टूबर, 2018 को, बैंक प्रबंधन ने समझाया कि उन्होंने उचित प्रबंधन के लिए अनुरोधकर्ताओं के ई-मेल को परियोजना प्रबंधन इकाई को भेज दिया है। अक्टूबर और नवंबर 2018 के बीच अतिरिक्त ई-मेल का आदान-प्रदान किया गया और 29 नवंबर, 2018 को, अनुरोधकर्ताओं और बैंक प्रबंधन ने प्रबंधन द्वारा एक और साइट यात्रा की योजना शुरू करने के लिए एक फोन मीटिंग की। फिर भी, अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि वे प्रबंधन की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त मानते हैं।

28. पैनल ने यह भी सत्यापित किया कि अनुरोध की विषय वस्तु वसूली के मुद्दों को नहीं उठाती है और, अनुरोध की प्राप्ति के समय, परियोजना 21.68 प्रतिशत हो चुकी थी। परियोजना की समापन तिथि 31 मार्च, 2020 है। पैनल ने इस अनुरोध में उठाए गए मुद्दों पर कोई सिफारिश भी नहीं की है।

अनुरोध का पंजीकरण

29. जैसा कि पैनल स्थापित करने वाले IDA प्रस्ताव ("प्रस्ताव") के पैरा 17 में प्रदान किया गया है, "*पैनल के अध्यक्ष अनुरोध प्राप्त होने पर कार्यकारी निदेशकों और बैंक के अध्यक्ष को तुरंत निरीक्षण के लिए सूचित करेंगे।*"[6] इस नोटिस के साथ, मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि मैंने 18 दिसंबर, 2018 को यह अनुरोध पंजीकृत किया है।

---

[6] पैनल स्थापना प्रस्ताव (**22** सितंबर**, 1993),** प्रस्ताव संख्या IDA **93-6,** **http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelMandateDocuments/Resolution1993.pdf**

30. पैनल के पंजीकरण का तात्पर्य है कि निरीक्षण के अनुरोध के गुण के संबंध में कोई निर्णय नहीं। जैसा कि प्रस्ताव के पैरा 18, और "*निरीक्षण पैनल की बोर्ड की दूसरी समीक्षा के निष्कर्षों*" ("1999 का स्पष्टीकरण") के पैरा 2 और 8 में दिया गया है, बैंक प्रबंधन को 21 कार्य दिवसों (25 जनवरी, 2019 तक) के भीतर पैनल प्रदान करना होगा, निरीक्षण के अनुरोध में उठाए गए मुद्दों की प्रतिक्रिया में। अनुरोध के जवाब में प्रबंधन को जिस विषय से निपटना है उसे 1999 के स्पष्टीकरण के पैरा 3 और 4 में निर्धारित किया गया है।

31. प्रबंधन प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, पैनल, जैसा 1999 के स्पष्टीकरण में उल्लिखित है और जैसा कि प्रस्ताव के पैरा 19 में प्रदान किया गया है, "निर्धारित करेगा कि क्या अनुरोध पैरा 12 से 14 [प्रस्ताव के] में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता है और क्या कार्यकारी निदेशकों को सिफारिश करता है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए या नहीं।"[7] इस अनुरोध को IPN अनुरोध संख्या RQ 18/07 निर्दिष्ट की गई है।

आपका भवदीय,

इमराना जलाल
अध्यक्ष

संलग्नक

श्री जिम योंग किम, अध्यक्ष
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन

द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अल्टरनेट्स
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन

(निरीक्षण पैनल और प्रबंधन दस्तावेजों के अनुवाद अनौपचारिक हैं और इच्छुक पार्टियों को सेवा के रूप में प्रदान किए जाते हैं। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। यदि हिंदी में अनुवाद का कोई भी हिस्सा अंग्रेजी में मूल पाठ के साथ असंगत है, तो अंग्रेजी अनुवाद प्रबल होगा।)

[7] Ibid.